उत्तर उजाला

बुधवार 15 मई, 2019

कृत्रिम सुख की बजाय, हमेशा ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिये। –अब्दुल कलाम

भारत-चीन एक साथ

एशिया उपमहाद्वीप के दो बड़े देश भारत और चीन के बीच विभिन्न स्तरों पर कड़ी प्रतिस्पर्द्धा दिखाई देती है। एशिया में चीन की बढ़ती ताकत को भारत से तगड़ी चुनौती मिल रही है। पर चीन इतना तो समझ चुका है कि आज वह भारत से युद्ध लड़कर उसे नहीं पछाड़ सकता है। भारत दुनिया में एक उभरती ताकत के रूप में स्वयं को स्थापित कर चुका है। यही वजह है कि विवादों पर बातचीत की पहल के साथ ही उसने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने पर जोर दिया है। वर्तमान बाजारवाद के दौर में वह भारत के बड़े बाजार की अनदेखी नहीं करना चाहता है। लेकिन अमेरिका ने एकतरफा ट्रेड वॉर छेड़कर दोनों देशों को एकजुट कर दिया है। अमेरिका की मनमानी का परिणाम है कि डब्ल्यूटीओ में विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक विवादों के निपटारे के लिए सुनवाई करने वाली अपीलेट बॉडी अप्रभावी हो गई है। अमेरिका ने जजों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इस संस्था में सात जज होते हैं, फिलहाल इसमें तीन जज ही बचे हैं। दिसंबर में दो और जजों की सेवानिवृत्ति के बाद सिर्फ एक जज ही बच जाएंगे। उसके बाद किसी भी मसले पर सुनवाई की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन में जो मुद्दे फंसे हैं, उनमें भारत और चीन की दो-दो शिकायतें प्रमुख हैं। भारत ने लोहा और स्टील के आयात पर अमेरिका द्वारा सेफगार्ड ड्यूटीज लगाए जाने के आदेश को चुनौती है। एक अन्य मामले में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा (रीन्यूएबल एनर्जी) पर अमेरिकी कदमों को चुनौती दी है। वहीं, चीन ने अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में शिकायत की है। साथ ही, चीन ने कुछ स्टील प्रॉडक्ट्स पर अमेरिका द्वारा ड्यूटी बढ़ाने के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल, करीब 70 देशों ने अमेरिका से जजों की नियुक्ति पर रोक हटाने की बार-बार गुहार लगाई है। यह दुर्लभ मामलों में एक है जिसमें भारत, चीन और यूरोपियन यूनियन एक तरफ खड़ा है। इसी क्रम में विश्व व्यापार संगठन के 22 विकासशील और सबसे कम विकसित सदस्य देशों की बैठक में भारत ने व्यापारिक मुद्दों पर सदस्य देशों की एकतरफा कार्रवाई से संबंधित कानून में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है। चीन और दक्षिण अफ्रीका भारत के इस कदम के समर्थन में हैं। इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा का एक प्रमुख बिंदु यह है कि यह विकासशील देशों के लिए विशेष प्रावधान हैं जिसे विशेष और विभेदकारी व्यवहार कहा जाता है। इसके तहत विकासशील देशों को समझौतों और वादों को लागू करने के लिए ज्यादा वक्त मिलता है। साथ ही, इसमें उनके व्यापारिक हितों की सुरक्षा के प्रावधान भी हैं। इस वैश्विक स्थिति में भारत और चीन का एकमत होना आश्चर्य की बात नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापारिक मसलों में अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी से चीन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है और दोनों देशों के बीच जारी व्यापारिक बातचीत विफल रही है। अमेरिका ने 5.6 अरब डॉलर मूल्य की आयातित वस्तुओं पर ड्यूटी बेनिफिट्स हटाकर भारत को भी व्यापारिक झटका दिया है। उसने चीन से आयातित वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया है। वहीं अन्य विकासशील देशों को भी वह बार-बार चेता रहा है। यूएस ट्रेड सेक्रटरी विल्बर रॉस ने अपने हालिया दिल्ली दौरे में भारत पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर अन्यायपूर्ण तरीके से आयात शुल्क लगाता है। बहरहाल, अमेरिका की एकपक्षीय कार्रवाई के खिलाफ बहुपक्षीय एकजुटता से भारत और चीन फायदे में रहेंगे। यदि भारत और चीन के नेतृत्व में विकासशील देश अपनी वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए एकजुटता दिखाकर अमेरिका को महत्व नहीं देते हैं तब मुश्किल में अमेरिका ही होगा। उसे अपने माल के खरीददार इन्हीं विकासशील देशों में मिलते हैं। आज अमेरिका दुनिया के देशों पर जिस तरह अपने हित में फैसले लाद रहा है उस स्थिति को बदलने के लिए भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की एकजुटता एक दिन अमेरिका को अपने फैसलों पर पुनर्विचार के लिए विवश करेगी।

धधक रहे जंगल

राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक जंगल लगातार धधक रहे हैं। एक जंगल में आग बुझाने की कोशिश की जाती है तब तक दूसरे जंगल भड़क उठते हैं। जगह जगह आग विकराल रूप धारण करती जा रही है। पिछले दो हफ्तों में ही जंगलों में आग की 623 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जबकि 15 फरवरी से 30 अप्रैल तक 88 घटनाएं हुई थी। इसके साथ ही इस फायर सीजन में अब तक वनों में आग की घटनाओं की संख्या 711 पहुंच चुकी है, जिसमें 992 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इस साल अप्रैल माह तक बीच बीच में बारिश होने से जंगलों में आग लगने की जो घटनाएं हो रही थी वे अधिक नहीं फैल सकी। अल्मोड़ा जिले के सल्ट ब्लाक के मानिला वन क्षेत्र में लगी आग ने रिहायशी इलाके के नजदीक जंगल में रखे गए लीसा स्टॉक को अपनी चपेट में ले लिया। वहां लीसे से भरे 150 टिन रखे गए थे। इनमें होने वाले विस्फोट से लोग सहम गये। साथ ही रतखाल बाजार व आसपास के क्षेत्रों में धुएं के काले गुबार छाये रहे। यही नहीं, पुरियाचौरा में गैस गोदाम के नजदीक भी आग पहुंच गई थी, जिस पर किसी तरह काबू पाया जा सका। पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल व चंपावत जिलों में दो दर्जन से अधिक स्थानों पर अभी भी आग भड़कने की सूचना है। श्रीनगर में एसएसबी की फायरिंग रेंज से लगे जंगल तक आग पहुंची है तो नैनीताल में आर्य भट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान (एरीज) और चंपावत में पूर्णागिरी मंदिर क्षेत्र से लगे जंगल भी सुलग रहे हैं। पौड़ी जिले के खोला, नैथाणा, झिंझनीसैंण, पैंडुला पांव, नाड़ी पांव, रुद्रप्रयाग जिले के बच्छणस्यूं, खांकरा, जखोली, बष्टी, टिहरी की भिलंगना घाटी के जंगलों में आग लगी है। नैनीताल के नजदीक तल्ला कृष्णपुर से लेकर ताकुला तक के जंगल धधक रहे हैं। हनुमानगढ़ी क्षेत्र में भी आग लगी है। चंपावत जिले के कई जंगलों में आग लगने की सूचना है। बागेश्वर के चंडिका मंदिर के पास भी जंगल धधक रहे हैं। भिलंगना, खोला और रुद्रप्रयाग क्षेत्र के जंगलों में आग से करोड़ों रुपये की वन संपदा नष्ट हो चुकी है। घनसाली क्षेत्र में तो पांच दिन से जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। इससे जंगल से सटे शहरी क्षेत्रों में समूचा वातावरण धुएं से भर गया है। ग्रामीणों के सामने चारा-पत्ती का संकट भी खड़ा हो गया है। वन विभाग के दावानल पर नियंत्रण के दावे हवा-हवाई साबित हो रहे हैं। वन विभाग के आंकड़ों के आंकड़ों के अनुसार इस फायर सीजन में अब तक जंगलों में आग की 491 घटनाएं हो चुकी है, जिसमें 676.835 हेक्टेयर जंगल तबाह हुआ है। 11.25 लाख रुपये की क्षति हुई है। कुमाऊं क्षेत्र में जंगल अधिक तेजी से सुलग रहे हैं, जहां आग की 317 घटनाएं हो चुकी हैं। गढ़वाल क्षेत्र में अब तक 149 और वन्यजीव परिरक्षण क्षेत्र में 25 घटनाएं सामने आई हैं। आग से नैनीताल, चमोली और ऊधमसिंहनगर जिलों में 11.26 हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया पौधरोपण भी तबाह हो गया। फायर सीजन से पूर्व ही जंगलों को आग से बचाने की तैयारी पूरी कर लेने का दावा वन विभाग कर रहा था। तब सवाल यह है कि जंगलों की आग पर नियंत्रण क्यों नहीं किया जा सका है। सच तो यह है यह सब तैयारी बंद कमरों में कागजों में ही की जाती है। विभाग के पास न तो पर्याप्त संसाधन हैं और न ही प्रशिक्षित कर्मचारी। फिर जंगलों को बचाने की इस मुहिम में स्थानीय लोगों को जोड़ने की पहल नहीं की जाती है। जब इन लोगों को जंगलों पर कोई अधिकार ही नहीं दिया जायेगा तब वे इन्हें बचाने का उत्साह क्यों दिखाएंगे। इसलिए जरूरी है कि वन नीति को बदला जाये। वनाग्नि के नियंत्रण के लिए व्यावहारिक स्तर पर कदम उठाये जायें।

श्रम का सम्मान

प्रेरक प्रसंग

एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन नगर की स्थिति का जायजा लेने के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई मजदूर एक बड़ा-सा पत्थर उठाकर इमारत पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं किंतु इतने मजदूरों के उठाने पर भी उठ नहीं पा रहा था। ठेकेदार उन मजदूरों को पत्थर न उठा पाने के कारण डांट रहा था। वॉशिंगटन ठेकेदार के पास आकर बोले, 'इन मजदूरों की मदद करो।' ठेकेदार रौब से बोला, 'मैं दूसरों से काम लेता हूं, मजदूरी नहीं करता।' यह जवाब सुनकर वॉशिंगटन घोड़े से उतरे और पत्थर उठाने में मजदूरों की मदद करने लगे। उनके सहारा देते ही पत्थर उठ गया और आसानी से ऊपर चला गया। इसके बाद वह वापस अपने घोड़े पर आकर बैठ गए और बोले, 'सलाम ठेकेदार साहब, भविष्य में कभी तुम्हें एक व्यक्ति की कमी महसूस हो तो राष्ट्रपति भवन में आकर जॉर्ज वॉशिंगटन को याद कर लेना।' यह सुनते ही ठेकेदार उनके पैरों पर गिर पड़ा। वॉशिंगटन बोले, 'मेहनत करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मजदूरों की मदद करने से तुम उनका सम्मान हासिल करोगे।

फिर नायक बनकर उभरे पटनायक

अरुण नैथानी

> **इस कुदरत के कहर का मुकाबला राज्य सरकार ने जिस सूझबूझ व कुशलता से किया, उसे पूरी दुनिया ने सराहा। एक-एक जान के लिये सरकार द्वारा संवेदनशीलता दर्शाना तथा बारह लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना बड़ी बात थी। जहां 1999 में आये महाचक्रवात में दस हजार जानें गई थीं वहीं इस बार यह आंकड़ा चालीस से कम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम ही मौकों पर विपक्षी मुख्यमंत्रियों की तारीफ करते नजर आते हैं, लेकिन आम चुनाव के दौरान उन्होंने नवीन पटनायक सरकार की सराहना की। एक व्यक्ति जो पचास साल की उम्र तक राजनीति से कोसों दूर रहा हो, और फिर जब राजनीति में आये तो राजनीति का होकर रह जाये, अचरज होता है।**

भले ही समुद्री चक्रवात फानी ओडिशा और निकटवर्ती राज्यों के लिये कष्टदायी व भय का प्रतीक रहा हो, मगर इन तूफानी हवाओं ने नवीन पटनायक की छवि निखार दी। इस कुदरत के कहर का मुकाबला राज्य सरकार ने जिस सूझबूझ व कुशलता से किया, उसे पूरी दुनिया ने सराहा। एक-एक जान के लिये सरकार द्वारा संवेदनशीलता दर्शाना तथा बारह लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना बड़ी बात थी। जहां 1999 में आये महाचक्रवात में दस हजार जानें गई थीं वहीं इस बार यह आंकड़ा चालीस से कम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम ही मौकों पर विपक्षी मुख्यमंत्रियों की तारीफ करते नजर आते हैं, लेकिन आम चुनाव के दौरान उन्होंने नवीन पटनायक सरकार की सराहना की।

एक व्यक्ति जो पचास साल की उम्र तक राजनीति से कोसों दूर रहा हो, और फिर जब राजनीति में आये तो राजनीति का होकर रह जाये, अचरज होता है। आज वे ओडिशा में लगातार चार बार मुख्यमंत्री रहने वाले पहले राजनेता हैं। हालांकि इस बार उन्हें भाजपा से कड़ी चुनौती मिल रही है, मगर नवीन के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में वे महीन कातते हैं। यह ठीक है कि नवीन पटनायक को राजनीति विरासत में मिली है, मगर उन्होंने राजनीति का नया मुहावरा गढ़ा है। उनके पिता बीजू पटनायक का राजनीति में अपना ऊंचा कद था। बीजू पटनायक राजनेता से पहले एक स्वतंत्रता सेनानी और वायुसेना अधिकारी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण अभियानों के लिये उन्होंने उड़ान भरी। बताया जाता है कि आजादी के बाद कश्मीर पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने हमला किया तो वे पंडित नेहरू के कहने पर 17 जवानों को लेकर श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरे थे। इन जवानों ने घुसपैठियों को खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीजू पटनायक कई देशों के नायक थे। जब उनका निधन हुआ तो उनके पार्थिव शरीर पर तिरंगे के अलावा रूस व इंडोनेशिया के ध्वज लिपटे थे। जीवन के शुरुआती पचास साल वे राजनीति से अलग-थलग रहे। विदेशों में उन्होंने अपने ढंग से जीवन जीया। किताबें लिखी और एक फिल्म में भी काम किया। अमेरिका में जान एफ. कनैडी की पत्नी से उनके अच्छे संपर्क रहे। इसके अलावा संगीत की दुनिया के नामी लोगों और भारत के कई बड़े पत्रकारों से उनके संबंध रहे। दून स्कूल में संजय गांधी उनके सहपाठी रहे। बाद में राजीव गांधी से भी उनके संबंध बहुत अच्छे रहे। सोनिया गांधी तक उनकी पहुंच दिग्गज कांग्रेसी नेताओं से अधिक रही। वर्ष 1996 में सांसद और फिर मंत्री बनने के बाद उनकी जो राजनीतिक यात्रा शुरू हुई, वह आज लगातार चार बार मुख्यमंत्री बनने तक जारी है। राजनीति में आने के बाद उनकी इस बात को लेकर आलोचना होती रही है कि उन्हें उड़िया बोलनी भी नहीं आती। वे अच्छा भाषण नहीं दे पाते। यूरोपीय शैली की धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलने वाले नवीन पटनायक का भाषण रोमन में लिखा जाता रहा। लेकिन राजनीतिक भ्रष्टाचार से आजिज जनता ने उनके उड़िया न बोलने को भी सहर्ष स्वीकारा। उन्हें उम्मीद थी कि वे राज्य के विकास को नई दिशा देंगे। उन्होंने एक ईमानदार राजनेता की छवि भी बनायी। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के दो दर्जन से अधिक मंत्रियों को कदाचार व अनुचित कारणों के लिये बाहर का रास्ता दिखाया। राजनीति में आने के बाद खादी के कुर्ते-पाजामे में नजर आने वाले नवीन पटनायक बेहद सुलझे व कम बोलने वाले राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन उनके राजनीतिक दांवों को समझना उतना ही जटिल है। समय पर पार्टी के महत्वाकांक्षी राजनेताओं, नौकरशाहों और अपने मित्रों को उन्होंने मौका मिलते ऐसे किनारे लगाया कि सब हैरत में पड़ गये।

जहां तक ओडिशा के विकास की बात है तो राज्य में कई तरह के अंतर्विरोध सामने नजर आते हैं। शिक्षा व्यवस्था में कोई आमूलचूल परिवर्तन तो नहीं हुआ मगर प्रतियोगी परीक्षाओं में ओडिशा की भागीदारी अव्वल है। स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ मगर राज्य के शहर साफ-सुथरे हैं। राज्य का औद्योगिक विकास बहुत उल्लेखनीय नहीं है मगर गरीबों के लिये उन्होंने तमाम ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो बहुत राहतकारी हैं। सस्ता अनाज व खाना देना इन योजनाओं का हिस्सा है। कहा भी जाता है कि योजनाएं लोकलुभावनी तो हैं मगर प्रगतिशील विकास की आधारशिला नहीं रखती। यह उनकी राजनीतिक मजबूती का ही खेल था कि राज्य में कांग्रेस लगातार हाशिये में जाती गई। अब पार्टी को भाजपा की तरफ से कड़ी चुनौती मिल रही है। पिछले निकाय चुनावों में भाजपा ने बीजू जनता दल का आधार कम किया। उत्तरी भारत में अपना जनाधार खिसकते देख भाजपा ने इस बार ओडिशा में पूरी ताकत झोंक रखी है। धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में राज्य भाजपा बदलाव के लिये जी-जान से जुटी है।

मेरी किसानी का सफर

सुभद्रा खापर्डे

> **श्रद्धेय श्री बनवारीलालजी के रहते हुए मैं दो या तीन बार निटाया गई थी। उस जमाने में कार्यकर्ताओं का बड़ा ही जलवा था। जन-आंदोलनों के दिन थे। वरिष्ठ गांधीवादी इन आंदोलनकारियों का समर्थन करते और उन्हें प्यार से प्रोत्साहित करते थे। उनके आश्रमों में बड़ी-छोटी बैठकें एवं कार्यशालाएं आयोजित किए जाते थे। गांधीवादी हमारे जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं के संग में सुकून महसूस करते थे। पर यह बात अब 25 साल पुरानी हो गई है। सरकार ने देखा कि जन-आंदोलनों के कार्यकर्ता कुछ ज्यादा कूद रहे हैं और इन्हें दबाना जरूरी है तो इसके लिए सभी राजनीतिक दल एक हो गए। कार्यकर्ताओं को जेलों और अदालतों के चक्कर में फंसा दिया गया एवं इस प्रकार अधिकारों की लडाई को दमन के जरिये धीमा कर दिया गया।**

ग्राम सेवा समिति, निटाया, (होशंगाबाद) में मुझे दिनांक 17 मार्च 2019 को स्वर्गीय बनवारीलालजी चौधरी स्मृति अन्न स्वराज सम्मान' दिया जाना तय हुआ था। मैं खुशी से भर गई और आश्चर्य भी हुआ की पता नहीं क्यों मेरा सम्मान करना चाहते हैं। वर्षों पुरानी बातें याद करने लगी। श्रद्धेय श्री बनवारीलालजी के रहते हुए मैं दो या तीन बार निटाया गई थी। उस जमाने में कार्यकर्ताओं का बड़ा ही जलवा था। जन-आंदोलनों के दिन थे। वरिष्ठ गांधीवादी इन आंदोलनकारियों का समर्थन करते और उन्हें प्यार से प्रोत्साहित करते थे। उनके आश्रमों में बड़ी-छोटी बैठकें एवं कार्यशालाएं आयोजित किए जाते थे। गांधीवादी हमारे जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं के संग में सुकून महसूस करते थे। पर यह बात अब 25 साल पुरानी हो गई है। सरकार ने देखा कि जन-आंदोलनों के कार्यकर्ता कुछ ज्यादा कूद रहे हैं और इन्हें दबाना जरूरी है तो इसके लिए सभी राजनीतिक दल एक हो गए। कार्यकर्ताओं को जेलों और अदालतों के चक्कर में फंसा दिया गया एवं इस प्रकार अधिकारों की लडाई को दमन के जरिये धीमा कर दिया गया।

ठहराव के इस दौर में मैं सोचने लगी कि मैं क्या कर सकती हूं। धीरे-धीरे इंदौर शहर की बस्तियों की गरीब औरतों के प्रजनन स्वस्थ्य पर काम करना शुरू किया। इस काम को करते हुये मैंने पाया कि औरतों की सेहत का खराब होना उनके रोजमर्रा के भोजन से भी जुड़ा हुआ है। मैं सोचने लगी कि उनके भोजन में क्या शामिल किया जाए ताकि उनकी पोषण की स्थिति में सुधार हो। उन्हें मैं दवाई के साथ बाजार में उपलब्ध सब्जी और फल खाने की सलाह देती थी। फिर मैंने देखा कि ये फल, सब्जियां एवं अन्य खाद्य पदार्थ जो बाजार में उपलब्ध हैं, सभी रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों से उत्पादित होकर सेहत के लिए हानिकारक हैं। इन खाद्यों से पोषण के साथ-साथ हमारे शरीर में जहर भी घुल रहा है। इसी को ध्यान में रखकर मैंने सोचा कि क्यों न भोजन में प्राकृतिक रूप से उत्पादित चीजों को शामिल किया जाए। इतना ही नहीं, इस बात की चेतना लाना भी बड़ी चीज होगी कि सिर्फ दवाई खाने से स्वास्थ्य नहीं सुधर सकता, बल्कि हमें हमारे खान-पान को भी सही करना होगा। पर क्योंकि बाजार में अधिकतर रासायनिक कृषि की उपज ही उपलब्ध है इसलिए मुझे खुद प्राकृतिक कृषि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने ग्राम पांडुतालाब, जिला-देवास में एक एकड़ जमीन खरीदी और उस पर देसी हिसाब से खेती करना प्रारम्भ किया। इस प्रकार की खेती पर लिखी डॉ. महेंद्र 'मधुप' की किताब खेती के वैज्ञानिक और अरुण डिके द्वारा प्रकाशित दाना पानी पत्रिका के अंकों को पढ़ा। मुझे समझ में आया कि अधिकतर लोग सही भोजन नहीं खा पाने की वजह से ही बीमार हैं। मैंने ठान लिया कि औरतों को प्राकृतिक खेती के गुणवत्ता-पूर्ण उत्पादों की ओर ले जाऊंगी जिससे कि उनकी सेहत में सुधार लाने में काफी मदद मिलेगी। हमने न केवल प्राकृतिक खेती शुरू की, बल्कि इसमें काम के लिए अधिकतर औरतों को ही बुलाया ताकि वे उनकी पारंपरिक देसी खेती को वापस अपना सकें और खुद की खेती में प्रयोग कर सकें। पिछले तीन साल से यही देसी तरीका अपनाया जा रहा है। बारिश के समय एक एकड़ में 25 किस्म के बीज बोये जाते हैं। प्रत्येक फसल का पकने का समय अलग होता है एवं सभी को उसके अनुसार अवेरना होता है। गेहूं, चना हो या बाजरा, कोदों सभी को हाथ से निकाला जाता है। खाने लायक दाल या चावल भी हाथ से ही बनाया जाता है। यहां तक कि हल्दी भी हाथ की घट्टी से पीसी जाती है। यह काम काफी मेहनत का है इसलिए महिलाएं अब इसमें अधिक रुचि नहीं दिखातीं, वे देशी तरीकों को छोड़ चुकी हैं। असल में आज ऐसी सोच नहीं रही कि शुद्ध खाना है क्योंकि लोग इसके लिए जरूरी मेहनत करने से डरते हैं। आजकल लोग मशीन की सहूलियत के आदी हो गए हैं जबकि पहले जमाने में मशीनें नहीं थीं तो लोग मजबूरी के कारण मेहनत करते थे और शुद्ध भोजन करते थे। इस शारीरिक मेहनत से स्वास्थ्य भी बना रहता था और खाने की गुणवत्ता भी बनी रहती थी। मशीनी सभ्यता के फलस्वरूप मनुष्य आराम प्रिय हो गए हैं एवं मेहनत प्रधान जिंदगी की ओर लौटना मुश्किल हो गया है। अब उन पुराने तरीकों को वापस स्थापित करने के लिए कुछ लोगों को मेहनत करना ही पड़ेगा।

आज मैं जो खेती कर रही हूं उसका सूत्र मेरे बचपन के दिनों में है। जब मैं 12 साल की थी तब मेरी मां गुजर गई थी और उसके बाद मैं मेरे पिताजी के साथ खेत का काम, घर का काम भी करती थी और स्कूल की पढ़ाई भी करती थी। हम अत्यंत गरीबी में जीते थे। इसलिए उच्च-माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भी रोजगार के अभाव में मुझे बीड़ी बनाना पड़ता था। आखिरकार मैं पीवी राजगोपाल जी द्वारा संचालित 'प्रयोग' संस्था में प्रशिक्षण के लिए इसलिए गई कि मुझे रोजगार चाहिए था न कि मुझे किसी तरह का सामाजिक कार्य करना था। वहां जाकर मुझे अच्छा खाना मिला तो मैं तृप्त हो गयी क्योंकि न जाने कितने दिनों से मुझे भरपेट भोजन नहीं मिला था। समय के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू कर अंततः मैं जन-आंदोलनों की कार्यकर्ता बन गई। इससे मेरा राजनीतिक, सामाजिक बदलाव का रुझान बना पर शुरुआत में मैं केवल दो वक्त के भोजन की ही सोच रही थी। मेरी मां गरीबी के कारण बिना इलाज के गुजर गई थी इसलिए मैंने महिलाओं के स्वास्थ्य का कार्य शुरू किया। महिलाओं को होने वाली प्रजनन स्वास्थ्य की समस्याओं के इलाज के लिए मैं उनकी बस्तियों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करती हूं जिसमें स्त्री-रोग विशेषज्ञ, नर्स, लैब टेकनीशियन आदि ले जाकर जांच के बाद दवाई दी जाती है। इस काम को करने से मुझे समझ आया कि महिलाएं अधिकतर अपनी प्रजनन तंत्र की परेशानियों को बिना किसी इलाज के सहन करती रहती हैं। यहां तक कि गर्भाशय बाहर आ जाने के बावजूद भी काम करती रहती हैं। पुरुषों को इस बात की कल्पना तक नहीं है कि महिलाओं को कितनी परेशानी होती है। अगर मालूम भी होता है तो भी नजर-अंदाज कर दिया जाता है क्योंकि वे पैसा खर्च करना नहीं चाहते। गरीब महिलाएं चुपचाप तब तक काम करती रहती हैं जब तक कि वह बिस्तर पर नहीं पड़ जाती। समाज और सरकार महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझते हैं एवं इसीलिए उनके प्रजनन तंत्र की गंभीर समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे-जैसे मैं महिला स्वास्थ्य का काम करती गई वैसे-वैसे चिकित्सकों की मदद से प्रजनन स्वास्थ्य की समझ बढ़ती गई। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं महिलाओं को इसके लिए तैयार करती थी कि वे अपनी अंदरूनी जांच करवाने के लिए सहमत हो जाएं ताकि उनका इलाज ठीक से हो पाये। अक्सर महिलाएं कहती थी कि वे स्वस्थ्य हैं, जबकि जांच के बाद पता चलता था कि उनके प्रजनन तंत्र में कुछ-न-कुछ समस्या है। इस काम के लिए हम समाज से संसाधन जुटाते हैं एवं इसमें बस्तियों की महिलाएं ही सर्वेक्षण से लेकर शिविरों के संचालन तक के काम में अग्रणी रहती हैं। औरतों का यह महत्वपूर्ण गुण है कि वे अपनी जरूरतों, परेशानियों को भुलाकर घर और परिवार को संभालने के लिए काम करती रहती हैं, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि समाज और पुरुष इसका फायदा उठाते रहें और औरतों की समस्याओं की अनदेखी करते रहें। खेती में भी पारंपरिक रूप से औरतों की अहम भूमिका थी। देसी बीजों का संरक्षण पहले औरतें ही करती थी। सूखी कड़वी लौकी को खोखला कर उसमें बीजों को रखने का काम औरतें ही करती थी ताकि वह खराब न हो। मेरी मां, दीवाली के लिए जो छोटे मटके आते थे, उन्हें साफ कर उसी में बीजों को रखकर ऊपर से गोबर और मिट्टी से ढंक देती थी। यहां तक कि मेरी मां सफेद कद्दू की बड़ी को भी इसी प्रकार बचाकर रखती थी। इस प्रकार बीज एवं अन्य खाद्य पदार्थ कभी खराब नहीं होते थे। अब औरतों का यह कार्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपना लिया है और उनकी भूमिका नगण्य हो गयी है, परंतु क्या हम सभी इसके लिए दोषी नहीं है? अगर हम लोग औरतों की संरक्षण एवं उत्पादन की भूमिका को नजर-अंदाज नहीं करते तो समाज और कृषि आज की दुर्दशा की स्थिति में नहीं होती। जिस दिन हम औरतों को तवज्जो देने लगेंगे उसी दिन देश का चित्र बादल जाएगा। मेरे खेत में मैं हल चलाना चाहती हूं परंतु मेरे साथ काम करने वाला आदिवासी पुरुष साथी कहता है कि औरतें अगर हल चलाएगी तो धरती पलट जाएगी। पर हम से ही तो धरती है तो वह कैसे पलट जाएगी। फिर मैंने सोचा कि गायों से हल चला सकते है क्या? तो कहा गया कि गाय स्त्री-रूपी है इसलिए उसे हल चलाने के काम में नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार समाज के सोच के कारण मेरे सामने हर तरह की रुकावटें आती हैं, परंतु देशी बीज और पोषण को विस्तारित करने के लिए ही मैंने खेती अपनाई है और उसपर कैसे काम करना है यह मेरा निर्णय है। किसी के कुछ कहने से मेरे इरादों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देश को भोजन देने वाला किसान आज रासायनिक खेती के कारण बदहाली में जी रहा है। एक तरफ रासायनिक खाद, बीज और कीटनाशक महंगे होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को उनके उत्पादों के लिए सही दाम नहीं मिल रहा है। असल में सरकारें रासायनिक खाद, संकरित बीज, कीटनाशक और बड़े बांध बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों को अधिक महत्व देती है, न कि किसानों की खुशहाली को। इसलिए आज भी रासायनिक खेती को ही दुनिया भर में विशाल मात्रा में अनुदान देकर फैलाया जा रहा है। यह जहरीली खेती जब तक नहीं बदलेगी तब तक किसानों को कम लागत वाली देशी खेती के गुर अपनाने नहीं दिया जाएगा। जाहिर है, ऐसे में किसान के साथ-साथ आम जनता भी जहर खाकर मरेगी।

दृष्टिकोण

मौसम की चुनौतियां

देश के एक बड़े हिस्से में भारी गर्मी पड़ रही है। कई शहरों का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। बढ़ते तापमान का जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है। कई जगहों पर तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अब हर साल इस मौसम में यही अहसास होता है कि इस बार गर्मी पिछले साल से ज्यादा है। मतलब यह कि गर्मी साल दर साल बढ़ रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 1901 के बाद साल 2018 में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, लेकिन अभी से यह यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल औसत तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। पिछले महीने मौसम की जानकारी देने वाली वेबसाइट एल डोरैडो ने दुनिया के सबसे गर्म 15 इलाकों की लिस्ट जारी की। ये सारी जगहें मध्य भारत और उसके आसपास की हैं। लिस्ट में जो 15 नाम शामिल हैं उसमें से 9 महाराष्ट्र, 3 मध्य प्रदेश, दो उत्तर प्रदेश और एक तेलंगाना का है। एक सामान्य राय है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि शहरों में बढ़ते निर्माण कार्यों और उसके बदलते स्वरूप के चलते हवा की गति में कमी आई है। एक राय यह भी है कि तारकोल की सड़क और कंक्रीट की इमारत ऊष्मा को अपने अंदर सोखती है और उसे दोपहर और रात में छोड़ती है। बढ़ती गर्मी से सीधा जुड़ा हुआ है जल संकट। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी ही सूखे जैसे हालात हो गए हैं, जबकि पिछले वर्ष इन राज्यों में अच्छी-खासी बरसात हुई थी। वर्ष 2018 में मॉनसून की स्थिति बेहतर रहने के बावजूद बड़े बांधों में पिछले वर्ष से 10-15 फीसदी कम पानी है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश के 91 जलाशयों में उनकी क्षमता का 25 फीसदी औसत पानी ही उपलब्ध है। दरअसल मार्च से मई तक होने वाली प्री मॉनसून वर्षा में औसत 21 प्रतिशत की कमी आई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में प्री मॉनसून वर्षा में 37 प्रतिशत की कमी रही जबकि प्रायद्वीपीय भारत में 39 पर्सेंट की कमी। हालांकि फोनी तूफान की वजह से हुई वर्षा ने मध्य भारत, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में इस कमी की भरपाई कर दी। लेकिन अल नीनो की वापसी के अंदेशे से इस बार मॉनसून के कमजोर होने की आशंका मंडरा रही है। मौसम का अनुमान करने वाली निजी संस्था स्काईमेट वेदर ने कहा कि अप्रैल में यह कमजोर होता नजर आया था, पर इसमें फिर मजबूती के लक्षण दिख रहे हैं। जो भी हो, प्रशासन को सतर्क हो जाना चाहिए। जून में खरीफ की बुवाई शुरू हो जाएगी। देखना होगा कि किसानों को कोई दिक्कत न हो। इसी तरह गर्मी से जानमाल की क्षति रोकने के लिए भी तमाम जरूरी उपाय करने होंगे।

खतरे की आहट

भविष्य के खतरे से अनभिज्ञ इंसान के क्रियाकलापों से पूरी दुनिया की वह जीव शृंखला संकट में है, जिस पर मानव जीवन का अस्तित्व टिका है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट में उन खतरों के प्रति आगाह किया गया है, जो मनुष्य की भौतिकतावादी सोच व विलासिता के जीवन से उपजी त्रासदी की देन हैं। कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग का जो डरावना स्वरूप हमारे सामने है, वह इसी खतरे की ओर इशारा करता है जो मनुष्य के अतीत व भविष्य के निर्धारण के कारकों से जुड़ा है। वनों का अंधाधुंध कटान, समुद्र में भारी प्रदूषण, मिट्टी व हवा की जीवनदायिनी शक्ति का ह्रास इसके मूल में है, जिसकी हम तमाम चेतावनियों के बावजूद अनदेखी कर रहे हैं। जीवों और पौधों की प्रजातियों के विनाश की जो गति पिछले दशकों में बढ़ी है, उतनी क्षति पिछले दस लाख सालों में भी नहीं हुई। पेरिस में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में संपन्न इस बैठक में 182 देशों के प्रतिनिधियों और 450 विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। विडंबना है कि आज इंसान जिस प्राकृतिक दुनिया को तेजी से समाप्त कर रहा है, उसी पर हमारी समृद्धि और अस्तित्व निर्भर है। दरअसल, संकट से निपटने के लिए हमें बड़े बदलावकारी परिवर्तनों के लिए तैयार रहना होगा। इसमें हमारे विलासिता के उपभोग पर अंकुश लगाने की जरूरत है। हमें जहां विकास को प्रकृति के अनुरूप ढालने की जरूरत है, वहीं अर्थव्यवस्थाओं का ढांचा भी बदलना होगा। कॉरपोरेट खेती के ढांचे को भी बदलने की जरूरत है, जिसके लिए जंगलों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता व पर्यावरण संरक्षण संगठन द्वारा 15 हजार स्रोतों से एकत्र एक हजार आठ सौ पेज की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मनुष्य की प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की प्रवृत्ति ने मानव के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए जरूरी ताजे पानी, स्वच्छ हवा व उत्पादक मिट्टी को भी संकट में डाल दिया है। लगातार बढ़ते तापमान को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है जो फिलहाल एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है और सदी के अंत तक तीन डिग्री बढ़ने की आशंका है। विडंबना यह है कि जलवायु परिवर्तन के प्रयास और जैव विविधता का विनाश एक-दूसरे को बढ़ाते हैं। औद्योगिक कृषि और वनों की कटाई से पारिस्थितिकीय तंत्र पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मानव निर्मित ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन समस्या को और विकट बना रहा है। हर साल ब्रिटेन के आकार के उष्ण कटिबंधीय वनों के कटान से जहां जैव विविधता का संकट गहराया है वहीं कार्बन डाइआक्साइड भी बढ़ रही है, जिसके चलते हजारों प्रजाति के जीव अपने मूल अधिवास से बेदखल कर दिये गये हैं। ग्लोबल वार्मिंग के संकटों ने इसमें इजाफा ही किया है। दुनिया के तमाम देशों के जंगलों में लगने वाली आग से दुर्लभ वन व जीव प्रजातियां खत्म होने के कगार पर हैं। मगर इसके बावजूद दुनिया में इस समस्या के समाधान के साझे प्रयास नहीं हो रहे हैं। इस भयावह संकट को गंभीरता से लेने की जरूरत है।

आपकी बात

सामंती सोच

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण अब तक समाज में पितृसत्तात्मक ढांचे का मौजूद होना है। यह न सिर्फ महिलाओं को राजनीति में आने से हतोत्साहित करता है बल्कि राजनीति के प्रवेशद्वार की बाधाओं की तरह काम करता है। एक तरफ जहां देश का संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता हैं, वहीं घर की महिलाओं को परिवार के पुरुषों के हिसाब से ही अपनी सोच बनानी पड़ती है। अगर महिला अपनी मर्जी से राजनीतिक सोच विकसित करती है तो उसका अपने ही लोगों द्वारा मनोबल गिराया जाता है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पितृसत्तात्मक सोच का अंत करना होगा।

देवेन्द्रराज सुथार, जालोर, राजस्थान

नजरिया बदलें

जब भी राज्यों व केंद्र में चुनाव होते हैं तो कोई भी दल महिलाओं को टिकट देने को राजी नहीं होता। महिलाओं को संसद और राज्यों की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल संसद में पेश भी किया गया था, लेकिन दलों में सहमति न बनने की वजह से ठंडे बस्ते में चला गया। एक दल ने तो केंद्र सरकार की नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा भी किया था। यदि इसे अमलीजामा पहनाया जाता है तो यह महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए सभी दल एक दिन महिलाओं के सशक्तीकरण में अपना योगदान देंगे।

रूप सिंह नेगी, सोलन

गौरैया

कहां चली गई सारी गौरैया
नजर कहीं नहीं आती।
उनकी मीठी सुरीली चीं-चीं
अब सुनने में नहीं आती।
रोशनदान में पंखे के ऊपर
अब वह घोंसला भी नहीं
बनाती।
कितना सूना सूना सा लगता
बिना गौरैया का आंगन।
जैसे खो गया हो अचानक
हमारा अपना कोई प्रियजन!

- ओमप्रकाश बजाज

शादी के बाद अपना आकाश

आज के बदलते दौर में लड़कियां उच्च शिक्षा हासिल कर रही हैं। गांव-देहात और कस्बों से निकलकर बड़े शहरों का रुख कर रही हैं। वह करियर को तवज्जो दे रही हैं, लिहाजा बड़ी-बड़ी कंपनियों में पैठ बना रही हैं। मगर, समस्या शुरू होती है शादी के बाद। हकीकत तो यह है कि लड़की की नौकरी पर कैंची चलाए जाने की शुरुआत तभी शुरू हो जाती है, जब उसके लिए रिश्ता ढूंढ़ा जाता है। सामान्य सोच वाले परिवारों में लड़के वालों की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि 'हम बहू से नौकरी नहीं कराएंगे। हमें घर संभालने वाली लड़की चाहिए।' तर्क दिया जाता है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। परिवार में भी उसे समझा दिया जाता है कि इतने साल नौकरी करके शौक पूरा कर लिया, अब गृहस्थी पर ध्यान दो। सामाजिक-पारिवारिक दबाव में लड़की कई बार नौकरी छोड़ भी देती है। मगर, शादी के बाद नौकरी छोड़ने का फैसला सरासर गलत है। न सिर्फ करियर के लिहाज से, बल्कि इसके अन्य भी पहलू हैं। जब हम महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं, तो ध्यान रखना होगा कि इसकी पहली सीढ़ी आर्थिक सशक्तीकरण है। लेकिन, शादी के बाद लड़की की आत्मनिर्भरता को खत्म करके, उसे पति पर निर्भर कर दिया जाता है।

इसे तभी तोड़ा जा सकता है, जबकि शादी के बाद भी लड़की अपनी नौकरी को जारी रखे। इससे वह आत्मनिर्भर होकर जिंदगी बिता सकेगी। वरना हर छोटी-छोटी जरूरत के लिए उसे अपने साथी पर निर्भर होना पड़ेगा। दूसरा, लड़की के कामकाजी होने पर घर के आर्थिक फैसलों में उसकी राय को तवज्जो दी जाती है। सामान्य रूप से देखा जाता है कि परिवारों में जब रुपये-पैसे की बात होती है, तो घरेलू महिलाओं को अक्सर दूर ही रखा जाता है। परिवार को चलाने में उसकी भी आर्थिक भागीदारी है, यह सोच उसे आत्मसंतुष्टि का अलग एहसास देगी। अगर शादी के बाद घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लड़की नौकरी छोड़कर अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग देती है, तो उसे जीवन में आत्म संतुष्टि का एहसास नहीं होगा, लिहाजा आंतरिक खुशी उससे कोसों दूर रहेगी। जाहिर है कि नौकरी करने से लड़की सिर्फ घर में बंद नहीं रहती, बल्कि देहरी के बाहर पैर रखने के बाद उसे बाहरी दुनिया की भी कई नई चीजें देखने और समझने का मौका मिलता है। इसके अलावा अपनी इच्छानुसार करियर बनाकर और शादी के बाद भी इसे जारी रखकर ही वह अपनी शिक्षा और योग्यताओं का सही उपयोग कर सकती है। आज के दौर में महिलाओं को न सिर्फ शादी से पहले नौकरी करने के सपने देखने चाहिए, बल्कि बाद में भी करियर को प्राथमिकता पर रखना चाहिए।

शिवांगी